



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 12 अगस्त, 1989/21 आवण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं 0 एल 0 एल 0 आर 0-10/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुप्रकृत उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश यूटिलाइजेशन आफ लैण्डस एक्ट, 1973 (1973 का 17)” के, संलग्न अधिग्रामणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अवैधिक हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
मचिव (विधि) ।

मैं, "दि हिमाचल प्रदेश यूटिलाइजेशन आफ लैण्ड्स एक्ट, 1973 (1973 का 17) के, राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ और यह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

राज्यपाल,  
हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश यूटिलाइजेशन आफ लैण्ड्स एक्ट, 1973 (1973 का 17)" के, उपर्युक्त राजभाषा पाठ को हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है और वह उक्त अधिनियम का राजभाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश भूमि-उपयोग अधिनियम, 1973

(1973 का 17)

(4 जून, 1973)

(1-8-1988 को यथा विद्यमान)

भारत गणराज्य के चौवीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि-उपयोग अधिनियम, 1973 है।  
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।  
 (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या मंदर्भ में विस्तृत न हो :—

(क) “कृषि वर्ष” से 16 जून या ऐसी अन्य तारीख में, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त करें, प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;  
 (ख) “कुलैक्टर” से उस जिले का कुलैक्टर अभिप्रेत है जहां भूमि स्थित है;  
 (ग) “भूमि” से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगरीय भूमि नहीं है और जिसका अधिभोग किसी नगर या ग्राम के निर्भाण स्थल के रूप में नहीं किया जाता, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है, जो इस अधिनियम से विचार किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई हो ;  
 (घ) “स्वामी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका भूमि में साम्पन्निक अधिकार है और इसके अन्तर्गत भोग बन्धकदार या पट्टेदार भी है ;  
 (ङ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;  
 (च) “अभिधारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, भूमि कुलैक्टर द्वारा पट्टे पर दी गई हो ;  
 (छ) “नगरीय भूमि” से नगर, निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि अभिप्रेत है।

3. (1) किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी, कुलैक्टर ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसकी काश्त पिछले दो कृषि वर्षों से नहीं की गई है, ऐसा नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की तारीख की तारीख से तीस दिन के भीतर यह कारण दर्शित करे कि भूमि पर खेती क्यों नहीं की गई है और यदि कुलैक्टर स्पष्टीकरण को समाधानप्रद नहीं पाता है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भूमि का तुरन्त कब्जा ले सकता है :—

परन्तु कुलैक्टर ऐसा नोटिस उस भूमि के सम्बन्ध में जारी नहीं करेगा—

(क) जो घासणी के रूप में रखी और प्रयुक्त की जा रही है और राजस्व अभिलेख

में उस रूप में वर्गीकृत की गई है; और

(ख) जो नोटिस की तारीख से ठीक पूर्व तार वर्ष तक की निरन्तर अवधि के लिए घासणी के रूप में प्रयुक्त की गई है, जहां वह राजस्व अभिलेख में उस रूप में अभिलिखित की गई है या नहीं:

परन्तु यह और कि कुलैक्टर ऐसा नोटिस ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जारी नहीं करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, नोटिस जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्वार्ती वर्ष में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुरक्षित की गई है, अर्थात्:—

- (क) जरामाह;
- (ख) खलिहान;
- (ग) सिंचाई टंकी;
- (घ) उद्यान;
- (ङ) निजी बन;
- (च) वास स्थान, कविस्थान या शमशान भूमि; और
- (छ) कोई अन्य लोक प्रयोजन।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए “घासणी” से किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसमें घास या चारावृक्ष या दोनों ही उगाए जा रहे हों।

(2) उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित नोटिस की तामील सम्यक् रूप में हुई समझी जाएगी यदि उसे स्वामी के प्रायिक या अन्तिम जात आवास स्थान पर दे दिया गया हो या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया गया हो।

स्वामी को प्रतिकर का संदाय । 4. जब किसी भूमि का धारा 3 के अधीन कब्जा लिया गया हो, तो स्वामी को भूमि के प्रतिकर के रूप में पट्टे का आधा धन दिया जाएगा।

कुलैक्टर द्वारा पट्टा । 5. (1) जब कुलैक्टर ने धारा 3 के अधीन किसी भूमि का कब्जा लिया हो, तो वह उसे खाद्य और चारे की फसल उगाने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निवन्धनों और ऐसी शर्तों पर पट्टे पर दे सकता है, जैसी वह ठीक समझे।

(2) साधारणतया ऐसा प्रत्येक पट्टा तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन पट्टे की अवधि का अवसान हो गया हो या धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन पट्टे का पर्यवसान किया गया है तो कुलैक्टर उप-धारा (1) में यथा उपबंधित उसे पट्टे पर दे सकेगा, किन्तु पट्टे की कुल अवधि दीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कतिपय मामलों में पट्टे का पर्यवसान करने की कुलैक्टर की शक्ति होगी । 6. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 5 के अधीन भूमि का पट्टा दिया गया है उसकी किन्हीं निवन्धनों और शर्तों को भंग करता है, तो उसके किन्हीं अधिकारों या उपायों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव डाले विना कुलैक्टर को पट्टे का पर्यवसान करने और भूमि का कब्जा लेने की शक्ति होगी।

करने की कुलैक्टर की शक्ति ।

(2) जहां कुलैक्टर द्वारा पट्टे का पर्यवसान कर दिया गया हो, वहां अभिधारी किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

7. (1) जहां कोई ऐसी भूमि, जिसका कवजा धारा 3 के अधीन कुलैक्टर द्वारा लिया गया है, पट्टे की अवधि के अवसान पर स्वामी को वापिस दी जानी है, तो कुलैक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकता जिसे भूमि का कवजा दिया जाए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को भूमि के कवजे का परिदान कुलैक्टर को ऐसे परिदान के बारे में मभी दायित्वों में पूर्णतः उन्मोचित करेगा, किन्तु उस भूमि के बारे में उन अधिकारों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो भूमि का कवजा संपूर्ण जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि की मम्पक् प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो।

(3) जहां वह व्यक्ति, जिसे किसी भूमि का कवजा दिया जाना है, नहीं मिलता है, और उसकी ओर से परिदान प्राप्त करने के लिए कोई भी अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति सशक्त नहीं है, वहां कुलैक्टर भूमि किसी महजदृश्य भाग पर इस वोषणा का एक नोटिस लगवाएगा कि भूमि निर्मुक्त कर दी गई है।

(4) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस जारी करने पर नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि के मम्पन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका परिदान उसके कवजे के हकदार व्यक्ति को दे दिया गया है और सरकार या कुलैक्टर, उस भूमि के बारे में उस तारीख के पश्चात् किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायी नहीं होगा।

(5) पट्टे की अवधि के अवसान पर इस अधिनियम के उपनियों के अधीन अभिधारी को पट्टे पर दी गई भूमि पर खाद्यान्न या चारे की फसल उगाने में असफल रहता है, वहां वह धारा 5 के अधीन नियत लगान के मंदाय के अतिरिक्त उस लगान के दुगने से अनधिक जाति नदन करने का दायी होगा।

8. जहां अभिधारी, उसे पट्टे पर दी गई भूमि पर खाद्यान्न या चारे की फसल उगाने में असफल रहता है, वहां वह धारा 5 के अधीन नियत लगान के मंदाय के अतिरिक्त उस लगान के दुगने से अनधिक जाति नदन करने का दायी होगा।

9. स्वामी या अभिधारी ने इस अधिनियम के अधीन देय सभी राशियां भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूल की जायेंगी।

खाद्यान्न या चारे की फसल उगाने में अभिधारी की असफलता के लिए जास्ति।

देय राशि का भू-राज-स्व की वकाया के रूप में वसूली योग्य होना।

10. कुलैक्टर इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि उसकी राय में युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

कुलैक्टर के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना।

कृत्यों का

11. कुलैक्टर इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों प्रत्यायोजन। का अपने जिले के राजस्व या पुनर्वासि विभाग के किसी अधिकारी को नाम या पद से प्रत्यायोजन कर सकेगा।

पटटे की

लिखित को

स्टाम्पित,

अनुप्रमाणित

या रजिस्ट्री-

कृत न

करना।

12. तत्प्रथा प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कुलैक्टर द्वारा पट्टे को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी लिखित को स्टाम्पित, अनुप्रमाणित या रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित नहीं होगा।

अपील और

पुनरीक्षण।

13. (1) कुलैक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जिसे कि आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करके अनुज्ञात करे, राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त आयुक्त को लिखित रूप में अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—पन्द्रह दिन की अवधि की संगणना करने के लिए, अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) ऐसी अपील की जाने पर, आयुक्त, मामले में अपील का विनिश्चय होने तक अग्रिम कार्यवाहियों को रोक सकेगा।

(3) आयुक्त, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो तो कुलैक्टर से अभिलेख मंगाने के पश्चात् स्वयं या कुलैक्टर के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे अपील का विनिश्चय कर सकेगा।

(4) राज्य सरकार या इस निमित उसके द्वारा प्राप्तिकृत आयुक्त किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में उसका या अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी के समक्ष लम्बित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा और पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(5) इस अधिनियम में यथा उपवन्धित किसाए, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी जक्ति के प्रयोग में दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कारबाई किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जायेगी।

वादों या

विधिक

कार्यवाहियों

का वर्णन।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन मद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियों किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध स्थित नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन मद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से पारित किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी।

15. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथार्थीत्र, विधान सभा के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल मिला कर दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनन्द्रियिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के टीक वाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाती है या वह विनाशक्ति करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने में, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. इस अधिनियम के अधीन स्थापित अभिवृतियों को हिमाचल प्रदेश अभिवृति और भू-सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

हिमाचल प्रदेश अभिवृति और भू-सुधार अधिनियम, 1972 के उपबन्धों से अधिनियम के अधीन अभिवृतियों की व्यावृत्ति।

17. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त “दि ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन आफ लैण्ड एक्ट, 1949 (1949 का 38)” का एतद्वारा निरसन किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना या बनाए गए किसी नियम सहित की गई कोई बात या कार्रवाई जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों में संगत हो, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जायेगी।

निरसन और व्यावृत्तियां।

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0 आर0-12/88.—हिमाचल प्रदेश के राजपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश प्रिवेन्शन आफ एक्स कम्यूनिकेशन एक्ट, 1955 (1955 का 1)” के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा छपानार को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश दते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि)।

## हिमाचल प्रदेश बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955

( 1955 का 8 )

( 4 अक्टूबर, 1955 )

( 1-8-1988 को यथा विचमना )

हिमाचल प्रदेश में बहिष्कार का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बहिष्कार निवारण अधिनियम, विस्तार और 1955 है ।  
प्रारम्भ ।

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएँ । 2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, —

( क ) "समुदाय" से ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसके सदस्य इस तथ्य के कारण सम्बद्ध हैं कि जन्म, धर्म परिवर्तन या किसी धार्मिक कृत्य के पालन द्वारा वे एक ही धर्म या धार्मिक पथ से सम्बन्ध रखते हैं, और जाति या उप-जाति इसके अन्तर्गत है, और

( ख ) "बहिष्कार" से व्यक्ति का किसी समुदाय से जिसका वह सदस्य है, का उस द्वारा या ऐसे सदस्य के रूप में उसकी ओर से, सिविल प्रकृति के बाद वैध रूप से प्रवर्तनीय अधिकारों या विशेषाधिकारों से वंचित करते हुए, निष्कासन अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, वैध रूप से सिविल प्रकृति के बाद द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार के अन्तर्गत, पद धारण करने या सम्पत्ति रखने या किसी धार्मिक स्थान पर उपासना करने या कब्र में दफनाने या शब्दाह का अधिकार, ऐसे तथ्य के होते हुए भी है ऐसे अधिकार का अवधारण पूर्णतः समुदाय के किन्हीं धार्मिक कृत्यों या गृहकर्म या नियम या प्रथा के प्रश्न के विनिश्चय पर निर्भर करता है ।

बहिष्कार का विधि-मान्य और प्रभावी न होना ।

शास्ति ।

3. लक्ष्मय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, किसी समुदाय के सदस्य का बहिष्कार विधिमान्य और प्रभावी नहीं होगा ।

4. कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है जो किसी समुदाय के किसी सदस्य के बहिष्कार या उसे अग्रसर करने की कोटि में आता हो, दोषसिद्धि पर, जुमनि से जो एक हजार रुपय तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टोक्त रण।—जब इस धारा के अधीन किए गए अपराध के लिए अभिकथित व्यक्ति कोई निकाय या व्यष्टियों का संगम है, तोहे वह निगमित हो या नहीं, यदि ऐसा अपराध ऐसे निकाय या संगम की तैयारी में किया गया अभिकथित है, तो कोई व्यष्टि जिमने वहाँ कार के विनियोग के पश्च में मन दिया है, अपराध करने वाला समझा जाएगा।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी वात के होने हुए भी, मैजिस्ट्रेट प्रथम पंक्ति के व्यापालय में अगर कोई व्यापालय, धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अधिनियम के अधीन अधिकारिता।

6. कोई व्यापालय धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित वातों में नहीं करेगा:—

- (क) उस तारीख से जिमको अपराध किया गया अभिकथित है, एक वर्ष के प्रवशन के बाद, और
- (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की, जो जिला मैजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, पूर्व अनुमति के बिना।

अपराध के संज्ञान का दंग।

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1988

सं 0 एल 0एल 0आर 0 8/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुप्रक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश टाल्फर आफ लैंड (रैगुनेशन) एक्ट, 1968 (1969 का 15)” के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपाल्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम को राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विविध)।

## हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968

(1969 का 15)

(31-7-1988 को यथा विद्यमान)  
(15 मई, 1969)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हित में भूमि के अन्तरण और उससे सम्बन्धित विषयों को विनियमित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) विस्तार और अधिनियम, 1968 है ।  
प्रारम्भ ।

(2) इस का विस्तार हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्रों पर है जो समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त भू-राजस्व अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ख) “सहकारी भूमि बंधक बैंक” से हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी भूमि बंधक बैंक अधिनियम, 1957 (1957 का 26) के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीड्यूक्ट सहकारी भूमि बंधक बैंक अभिप्रेत है;
- (ग) “सहकारी सोसाइटी” से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीड्यूक्ट सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (घ) “उपायुक्त” से किसी जिला के सम्बन्ध में, उम जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है;
- (ङ) “वित्त आयुक्त” से हिमाचल प्रदेश का वित्त आयुक्त अभिप्रेत है;
- (च) “भूमि” से भू-सतह का प्रभाग, अभिप्रेत है, जाहे वह पानी के नीचे हो या नहीं, और इसके अन्तर्गत ऐसे प्रभाग से बढ़ किसी चीज से बढ़ या स्थाई रूप से जकड़ी हुई सभी चीजें हैं, किन्तु खनिज, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम, इमारती लकड़ी, वृक्ष और उगती फसलें और धारा इसके अन्तर्गत नहीं हैं;
- (छ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रत है;
- (ज) “अनुसूचित जाति” के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 क खण्ड (25) में इस के हैं;
- (झ) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

3. (1) किसी अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, भिन्नाय उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुज्ञा से, किसी भूमि में अपना हित, विक्रय वंशक, पट्टे, दान के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को, जो ऐसा जनजाति से सम्बन्ध न रखता हो, अन्तरित नहीं करेगा :

भूमि के अन्तर्गत का विनियमन ।

परन्तु इस उपधारा की कोई भी वात निम्नलिखित द्वारा किसी अन्तरण को लागू नहीं होगी :—

- (क) किराए पर इमारत के पट्टे के रूप में;
- (ख) क्रण प्राप्त करने के लिए, किसी महकारी भूमि वंशक वैक या किसी महकारी भोसाइटी को वंशक द्वारा, जिस के मध्यी या अविकांश सदस्य किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति हैं;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन, अर्जन द्वारा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि में हित सम्बन्धी किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा ।

4. (1) किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में अपने हित का ऐसी जनजाति से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति को अन्तरण करना चाहता हो, ऐसे अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मंजूरी के लिए, उपायुक्त को आवेदन कर सकेगा ।

भूमि अन्तरण की अनुज्ञा के लिए आवेदन ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन विहित प्रक्रिया में किया जाएगा और विहित विशिष्टियों से युक्त होगा तथा इसके साथ ऐसी फीम दी जाएगी जो विहित की जाए ।

(3) अनुज्ञा की मंजूरी के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उपायुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा भूमि को अन्तरित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इन्कार कर सकेगा :

परन्तु जहां अनुज्ञा से इन्कार किया जाता है वहां उपायुक्त ऐसे इन्कार के कारण अभिलिखित करेगा ।

(4) इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने से पूर्व, उपायुक्त निम्नलिखित मामलों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

- (क) आवेदक की वित्तीय स्थिति;
- (ख) आवेदक की शारीरिक दशा और आयु;
- (ग) प्रयोजन जिसके लिए अन्तरण करना प्रस्तावित है; और
- (घ) ऐसे अन्य सुसंगत विषय जैसे उपायुक्त मामल की परिस्थितियों में ठीक समझे ।

5. (1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि के अन्तरण के परिणामस्वरूप, किसी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी व्यक्ति का उस भूमि पर कब्जा पाया जाता है, तो उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति पर नोटिस के तारीख से नव्वे

बेदखली ।

दिन के भीतर भूमि को खाली करने की और ऐसी भूमि पर बनाई गई किसी इमारत; बाड़ या किसी अन्य संरचना को हटाने की अपेक्षा करत हुए, नोटिस की नामीन कर सकेगा :

परन्तु यदि ऐसे अर्जन के समय भूमि पर वास्तविक रूप में उगती हुई फसल हो, तो ऐसा व्यक्ति, जब तक फसलें काट नहीं दी जातीं, भूमि पर कब्जा रख रहने का हकदार होगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसको उपधारा (1) के अधीन अध्यवेक्षा की जाती है, ऐसी अध्यवेक्षा का अनुपालन करने को आवश्यक होगा ।

अपील । 6. (1) धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यक्ति, आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि आयुक्त न हो, तो ऐसी अपील वित्त आयुक्त को होगी;

परन्तु यह और भी कि, यथास्थिति, आयुक्त या वित्त आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों में समय पर अपील दाशर करने से निवारित था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान क पश्चात् भी, अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, यथास्थिति, आयुक्त या वित्त आयुक्त, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील को, यथाशक्य ग्रीष्म, निपटाएगा ।

आदेशों की अन्तिमता । 7. धारा 6 के अधीन अपील में, यथास्थिति, आयुक्त और वित्त आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश, और कबल ऐसे आदेश के अधीन रखते हुए, उपायुक्त द्वारा धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिया गया आदेश, अन्तिम होगा ।

अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भूमि में धारित अधिकार, हक या हित, किसी व्यायालय की अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध न रखने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क या वच जाने के वायित्व के अधीन नहीं होंग, सिवाय तब जब डिक्री या आदेश के अधीन देय रकम राज्य सरकार या किसी सहकारी भूमि बंद्रक वैक या सहकारी सोसाइटी को देय है ।

शास्ति ।

9. यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या धारा 5 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन दुष्प्रियत करता है, तो वह जुमाने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, अन्तिक्रित जुमाने से जो ऐसे प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकता, दण्डनीय होगा ।

10. (1) गाज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के नियम बनाने प्रयोजन के लिए नियम बना सकती ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले विना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

- (क) धारा 4 के अधीन अनुज्ञा दी जाने के लिये आवेदन का प्रस्तुप, विशिष्टियां जिनसे यह युक्त होगा, फीस जो इसके साथ दी जाएगी और ऐसी फीस को जमा करने की गति; और
- (ख) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए ।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।